



आम आदमी पार्टी की नीति : शिक्षा पर क्रांतिकारी परिवर्तन

अमरेन्द्र चौधरी

शोध छात्र, दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

Date of Submission: 05-08-2022

Date of Acceptance: 18-08-2022

सारांश :

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का उद्देश्य आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये सुधार, शिक्षा का अवलोकन करना है। वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने संविधान अवज्ञा आन्दोलन की शुरुआत की तब नमक जैसी बुनियादी वस्तु के लिए पूरा देश उनके पीछे जा खड़ा हुआ। वर्तमान समय में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा के वही महत्व है जो वर्ष 1930 में नमक का था। विगत कुछ वर्षों से दिल्ली के शिक्षा मॉडल ने दुनिया भर के तमाम विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ एडवर्ड इवरेट ने कहा था कि, "एक प्रशिक्षित सेना की अपेक्षा शिक्षित नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा अधिक बेहतर ढंग से कर सकते हैं।" मौजूदा समय में कहा जाए तो लम्बे समय से दो प्रकार के शिक्षा का स्वरूप प्रयोग किये जा रहे हैं, पहला कुलीन वर्ग का शिक्षा मॉडल और दूसरा आम जनता का शिक्षा मॉडल। किन्तु राजधानी में उक्त दो शिक्षा मॉडल के बीच के अन्तर को कम करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली के शिक्षा मॉडल का दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। अतः आम आदमी पार्टी ने राजधानी में सरकार बनाते ही शिक्षा पर जोर देकर काम करना प्रारम्भ किया। दिल्ली में साकार बनने के समय से आज तक तक वहाँ के विद्यालयों एवं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया गया, जिनका अध्ययन व्यवस्था हम प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा हमें न केवल अपनी समस्याओं के बेहतर एवं नवीन समाधान खोजने में मदद करती है बल्कि यह व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर में सुधार करने और समाज को व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से चलाने में भी सहायक है। शिक्षा के माध्यम से गरीबी को समाप्त कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश का प्रत्येक नागरिक भारत के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। अतः दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाते ही राज्य में शिक्षा का एक मॉडल का विकास किया है जो मुख्यतः पाँच घटकों पर आधारित है :-

4 पाठ्यक्रम में सुधार :-

पिछले कई वर्षों के आकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकारी विद्यालयों में 9वीं कक्षा में असफलता दर 50 प्रतिशत से भी अधिक है। आधारभूत कौशल के अभाव को

1 स्कूल के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन :-

प्रदेश में सरकार बनाने के बाद इस दल ने बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन किया, बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूल न केवल प्रशासन और सरकार की उदासिनता को दर्शाते हैं, बल्कि इनसे पढ़ने एवं पढ़ाने को लेकर छात्रों तथा शिक्षकों के उत्साह में भी कमी आती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सर्वप्रथम स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रुम, आडिटोरियम, प्रयोगशाला और सुसज्जित नई कक्षाओं का निर्माण किया गया। आकड़ों के अनुसार दिल्ली सरकार ने वर्ष 2017-18 में दिल्ली के विद्यालयों में कुल 10,000 कक्षाओं का निर्माण कराया था, अपने बजट का 25 प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया है। इसके अलावा सरकार ने प्राधान्यापकों और शिक्षकों से स्कूलों की स्वच्छता, रख-रखाव और मरम्मत आदि के बोझ को कम करने के लिए सभी विद्यालयों में एक प्रबंधक की नियुक्ति की है।

2 शिक्षकों और प्राधान्यापकों का क्षमता निर्माण :-

दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और प्लड अहमदाबाद जैसे उत्कृष्ट संस्थानों में कार्यरत विद्वानों से सीखने का अवसर प्रदान किया गया। वर्ष 2016 में प्राधान्यापक नेतृत्व विकास की शुरुआत की गई, जिसे 10 प्राधान्यापक का एक समूह प्रत्येक महिने में एक बार विद्यालय में नेतृत्व संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं।

3 विद्यालय प्रशासन को जवाबदेह बनाया :-

दिल्ली के सरकारी विद्यालय मुख्य रूप से अपनी अनुशासनहीनता के लिए काफी प्रसिद्ध है, इस चुनौति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने त्रि-स्तरीय निगरानी एवं तंत्र स्थापित किया, जिससे शिक्षा मंत्री ने स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण किया।

सर्वसम्मति से इसका मुख्य कारण स्वीकार किया गया। नियमित शिक्षा गतिविधियों की शुरुआत की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित का कौशल सीखें। इसी



प्रकार नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु " हैप्पिनेस पाठ्यक्रम " की शुरुआत की गई है। कक्षा 9 से 12 तक 'उद्यमशीलता पाठ्यक्रम ' की शुरुआत की गई।

5 निजी विद्यालयों की फीस में स्थिरता :-

उल्लेखनीय है कि उक्त चारो घटकों ने केवल दिल्ली के केवल सरकारी विद्यालयों को प्रभावित किया जबकि दिल्ली के निजी विद्यालयों में भी काफी अधिक संख्या में विद्यार्थी मौजूद है। ये विद्यालय वार्षिक आधार पर 8-15 प्रतिशत फीस की वृद्धि करते थे। सरकार ने सभी निजी विद्यालयों के लिए यह अनिवार्य किया कि वे फीस प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व किसी भी एक अधिकृत चार्टर्ड एकाउंटेंट से उसकी जांच करायेगें।

आम आदमी पार्टी ने अपनी 5 साल की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत के समय पार्टी प्रमुख ने कहा कि सबसे पहले पहला काम है शिक्षा। इस देश के अन्दर 70 साल में शिक्षा के क्षेत्र को कबाड़ा बना दिया गया। इस दल ने कुछ साल के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। इस दल ने शिक्षा के बजट को तीन गुना बढ़ा दिया। 6600 करोड़ का बजट आज 1560 करोड़ कर दिया गया है। 20,000 से ज्यादा नये क्लास रूम बनवाये। आज के समय परिणाम निजी विद्यालयों से अच्छा सरकारी विद्यालयों में आ रहा। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 500 नये विद्यालयों के निर्माण का वादा किया था, जिसमें से अधिकांश विद्यालय का निर्माण हो चुका है।

उपसंहार :-

आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किये हैं, इस दल ने कुछ सालों में शिक्षा की तस्वीर को बदल दिया है। इस दल के सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली विद्यालयी शिक्षा बोर्ड के गठन से लेकर देशभक्ति स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया है। दिल्ली देश का एकलौता राज्य है, जहाँ विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। करीब 2.5 लाख बच्चों ने निजी स्कूलों से नाम निकलवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया।

है। सरकारी स्कूलों में किये जा रहे बदलाव की गूँज तो विदेशों तक पहुँची है। विश्वस्तरीय शिक्षा देने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड का गठन का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से समझौता किया।

मूलशब्द -

शिक्षा, स्कूल, दल, सरकार

सन्दर्भ टिप्पणी :

1. दिल्ली का शिक्षा मॉडल; दृष्टि द विजन, 13 फरवरी 2020
2. आफिशियल वेबसाइट, aamaad miparty.org
3. श्रुति मेनन, बीबीसी न्यूज, 30 जनवरी 2020
4. विकास कुमार, अमर उजाला नई दिल्ली 16 फरवरी 2022